भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.1330

(जिसका उत्तर सोमवार 8 दिसंबर, 2025 /17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)

1330. श्री मनीश तिवारी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 से अब तक 10,000 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में वर्षवार कुल योगदान कितना रहा है;

(ख) इस अवधि के दौरान देश के 11 सबसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों ने विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कारोबार के हिसाब से कितना निवेश किया है;

(ग) इन निवेशों के कारण उत्पन्न हुए नए रोजगार अवसरों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन निजी निवेशों के क्षेत्रीय वितरण एवं सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार समान निवेश वृद्धि सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा एवं सेमीकंडक्टर जैसे उभरते विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, वर्ष 2014-15 से कुल सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में निजी निगमों के योगदान का विवरण निम्नानुसार है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
₹ लाख करोड़ में, मौजूदा कीमतें										
सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	37.5	39.6	43.4	48.2	55.7	57.2	54.2	69.8	84.0	91.7
निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ	13.5	15.9	16.6	17.2	19.0	21.2	19.2	24.2	29.7	29.7
निजी वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7
निजी निगमों द्वारा कुल जीएफसीएफ	13.7	16.3	16.9	17.4	19.4	21.7	19.8	24.6	30.2	30.3
कुल जीएफसीएफ में प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में										
निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ	35.9	40.3	38.2	35.7	34.1	37.1	35.4	34.6	35.4	32.4
निजी वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ	0.8	1.0	0.8	0.5	0.7	0.8	1.1	0.7	0.6	0.7
निजी निगमों द्वारा कुल जीएफसीएफ	36.6	41.3	39.0	36.2	34.9	37.9	36.5	35.3	36.0	33.1

10,000 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जीएफसीएफ में किए गए कुल योगदान, तथा 11 सबसे बड़े कारपोरेट समूहों द्वारा किए गए निवेश और उससे उत्पन्न रोजगार के विवरण, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं।

(घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में रोजगार के आकार, पूंजी निवेश, सकल उत्पादन और निवल मूल्यवर्धन जैसी प्रमुख विशेषताओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

(ङ) और (च): सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग (ऑटोमेटिक रूट) के माध्यम से 100% एफडीआई सहित देश में उभरते विनिर्माण क्षेत्रों में समान निवेश वृद्धि सुनिश्चित करने और अधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस), व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना और समर्पित भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शामिल हैं। इसी तरह, भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तत्परता से अपनाने और विनिर्माण (फेम) और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) जैसी योजनाओं की सहायता से नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, जलवायु-अनुकुलन और संधारणीय उद्यमों में निवेश में तेजी लाने के लिए उपाय लागू किए गए हैं। इसके अलावा, हाल के बजटों में, सरकार ने रोजगार-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई लक्षित उपायों की घोषणा की है, जिनमें फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए केंद्रित (फोकस) उत्पाद योजना, खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शामिल हैं।

*****